[2025] 8 एस.सी.आर. 1174 : 2025 आई.एन.एस.सी 1027

इकबाल अहमद (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण एवं अन्य

बनाम

अब्दुल शकूर

(सिविल अपील संख्या - 10458/2010)

22 अगस्त 2025

[पामिडिघंटम श्री नरसिम्हा और

अतुल एस चंदुरकर, * जे जे]

विचारणीय मुद्दा

यह प्रश्न उठा कि क्या अपीलीय न्यायालय के लिए सी.पी.सी. के आदेश XLI नियम 27(1) के तहत अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु की गई प्रार्थना पर निर्णय देने से पूर्व, पक्षों के अभिवचनों पर विचार करना आवश्यक है।

शीर्ष टिप्पणियाँ †

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश XLI नियम 27(1) - अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना - आदेश XLI नियम 27(1) के तहत अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए की गई प्रार्थना पर निर्णय देने से पहले, अपीलीय न्यायालय द्वारा पक्षों के अभिवचनों पर विचार करना - आवश्यकता - विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में, करार के विशिष्ट पालन (**specific performance**) के लिए पारित डिक्री - प्रत्यर्थी द्वारा अपील, और अपील के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी ने अपील के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग करते हुए आदेश XLI नियम 27(1) के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया - अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य पर विचार करने के बाद, उक्त डिक्री को उलट दिया - इसकी वैधता/बनाए रखे जाने की स्थिति:

अभिनिर्धारित: हाई कोर्ट द्वारा दिया गया फ़ैसला कानून की नज़र में सही नहीं है - हाई कोर्ट ने डिक्री को पलटते हुए, अतिरिक्त सबूत पेश करने के लिए आदेश XLI नियम 27(1)के तहत दी गई अर्ज़ी पर विचार किया, लेकिन यह जांच नहीं की कि क्या पेश किए जाने वाले अतिरिक्त सबूत, प्रतिवादी के लिखित बयान में दिए गए तर्कों (pleadings) से मेल खाते हैं - यह विचार करने से पहले कि क्या कोई पक्ष आदेश XLI नियम 27(1)के तहत अतिरिक्त सबूत पेश करने का हकदार है, सबसे पहले उस पक्ष के तर्कों की जांच करना ज़रूरी होगा, ताकि यह पता चल सके कि क्या पेश किया जाने वाला मामला, रिकॉर्ड पर लाए जाने वाले अतिरिक्त सबूतों का समर्थन करता है - इस संबंध में ज़रूरी तर्कों के

* लेखक

अभाव में, किसी पक्ष को अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति देना एक बेकार की कवायद होगी; और यदि ऐसे सबूत पेश भी किए जाते हैं, तो उनका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सबूतों पर विचार करना शायद कानूनन सही न हो - इसलिए, आदेश XLI नियम 27(1) द्वारा निर्धारित शर्तों के पूरा होने के अलावा, अपीलीय अदालत के लिए उस पक्ष के तर्कों पर विचार करना भी ज़रूरी होगा, जो ऐसे अतिरिक्त सबूत पेश करना चाहता है - केवल इसके बाद ही, जब अदालत इस बात से संतुष्ट हो जाए कि आदेश XLI नियम 27(1) के प्रावधानों के अनुसार मामला बनता है, तभी ऐसी अनुमति दी जा सकती है - हाई कोर्ट द्वारा यह जांच न किए जाने के कारण, उसने उत्तरदाताओं द्वारा अतिरिक्त सबूत पेश करने के लिए दी गई अर्ज़ी को मंज़ूर करके एक गलती की है - इसलिए, इस मामले पर हाई कोर्ट द्वारा फिर से विचार किए जाने की ज़रूरत है - हाई कोर्ट द्वारा दिया गया फ़ैसला और आदेश रद्द किया जाता है - कार्यवाही को हाई कोर्ट के पास वापस भेजा जाता है। [पैरा 7-10]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

अनिल राय बनाम बिहार राज्य **[2001] अनुपूरक 1 एस.सी.आर 298** : **(2001) 7 एस.एस.सी 318;** रतिलाल झावरभाई परमार और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य, **2024 आई.एन.एस.सी 801 : [2024] 10 एस.सी.आर 2227;** बछराज नाहर बनाम नीलिमा मंडल और अन्य **[2008] 14 एस.सी.आर 621 : ए.आई.आर 2009 एस.सी 1103;** भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन और अन्य **[2012] 8 एस.सी.आर 35 : (2012) 8 एस.एस.सी 148** - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; साक्ष्य अधिनियम, 1872.

प्रमुख शब्दों की सूची

अपीलीय न्यायालय; अभिवचन; अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना; अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना; करार के विशिष्ट पालन का आदेश; गृह कर मांग रजिस्टर; भार-मुक्त प्रमाण पत्र; विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति और नगर सर्वेक्षण पृष्ठांकन; मामले को वापस भेजना।

मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 10458/2010

आर.एफ.ए संख्या 440/2000 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु के दिनांक 30.12.2008 के निर्णय और आदेश से।

पार्टियों में उपस्थिति

अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्तागण: राघवेंद्र श्री अतसा, वरिष्ठ वकील, एन.के. वर्मा, सुश्री अंजना चन्द्रशेखर।

उत्तरदाता के लिए अधिवक्तागण: सुश्री महालक्ष्मी पावनी, वरिष्ठ वकील मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी, सुश्री आयशा सिद्दीकी, बी.एस. रंदावा, सुश्री सकीन क्विदवई, मोहम्मद सलमान सिद्दीकी, अमन आनंद, सुश्री प्रबीशा प्रदीप, नीलेश्वर पावनी, सुश्री शौर्य मिश्रा, मोहम्मद फरमान।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

अतुल एस. चंदुरकर, जे.

1. इस सिविल अपील में शामिल संक्षिप्त मुद्दा यह है कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XLI नियम 27(1) के प्रावधानों के तहत अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए की गई प्रार्थना पर निर्णय देने से पहले, अपीलीय न्यायालय के लिए पक्षों के अभिवचनों पर विचार करना आवश्यक है?

2. मामले अपीलकर्ता वे वादी हैं जो सफल नहीं हो पाए, और वे 20.02.1995 के समझौते के विशिष्ट पालन (specific performance) के उस आदेश को पलटे जाने से व्यथित हैं, जिसे ट्रायल कोर्ट ने पारित किया था। अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादी-प्रतिरक्षाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद उक्त आदेश को पलट दिया है।

2.1. अपीलकर्ताओं - वादियों का यह मामला है कि 20.02.1995 को, प्रतिवादी - डिफेंडेंट ने ₹10,67,000 के मूल्य पर अपनी मकान की संपत्ति बेचने के लिए एक समझौता किया। समझौते की तारीख को ₹2,50,000 की राशि का भुगतान किया गया, जबकि ₹2,50,000 की अतिरिक्त राशि का भुगतान 30.03.1995 को किया गया। यह समझौता डेढ़ वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाना था। उक्त समझौते के अनुसार, यदि प्रतिवादी खाली कब्ज़ा देने की स्थिति में नहीं होता, तो देय मूल्य ₹8,67,000 होता।

2.2. वादीगण ने 18.04.1996 को प्रतिवादी को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उससे विक्रय-पत्र निष्पादित करने के लिए कहा गया था। इस

नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद, 11.07.1996 को वादीगण द्वारा एक तार-नोटिस जारी किया गया। तत्पश्चात्, 19.07.1996 को वादीगण ने दिनांक 20.02.1995 के करार के विशिष्ट पालन के लिए वाद दायर किया।

2.3. वाद-पत्र में वादियों द्वारा यह अभिवचन किया गया था कि उन्होंने वाद-सम्पत्ति को क्रय करने के उद्देश्य से अपनी अन्य अचल सम्पत्तियों का व्ययन कर दिया था, जिसका उपयोग वे अपने स्वयं के अधिभोग हेतु करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त, यह भी अभिवचन किया गया था कि वादीगण करार के अंतर्गत अपने हिस्से के दायित्वों का निर्वहन करने हेतु सदैव तत्पर एवं इच्छुक थे, तथा शेष प्रतिफल राशि उनके पास उपलब्ध थी।

2.4. प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान में, वादियों द्वारा प्रस्तुत मामले को अस्वीकार कर दिया गया। प्रतिवादी के अनुसार, उसने अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए वादी संख्या 1 से ₹1,00,000 की राशि उधार ली थी, और 18.02.1995 को खाली स्टांप पेपरों पर उसके हस्ताक्षर लिए गए थे। यद्यपि उसने स्टांप पेपरों पर दो स्थानों पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया, किंतु उसने अन्य हस्ताक्षरों से इनकार कर दिया। जहाँ तक वादियों के इस दावे का प्रश्न है कि उन्होंने वाद-संपत्ति को खरीदने के लिए अपनी अचल संपत्तियों को बेच दिया था, प्रतिवादी ने कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वादियों ने ऐसा किया था।

2.5. वादी नंबर 1 ने खुद की और दो अन्य गवाहों की गवाही करवाई। प्रतिवादी ने ट्रायल कोर्ट के सामने खुद की गवाही दी। ऊपर बताए गए सबूतों पर विचार करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने यह माना कि वादियों ने यह साबित कर दिया था कि प्रतिवादी के साथ 20.02.1995 को बिक्री का एक समझौता किया गया था। इसके अलावा, यह भी माना गया कि वादियों ने अपनी तत्परता और इच्छाशक्ति साबित कर दी थी। ट्रायल कोर्ट ने वादियों के पक्ष में अपने विवेक का इस्तेमाल किया और प्रतिवादी द्वारा पेश किए गए सबूतों को अविश्वसनीय मानते हुए, 19.02.2000 को विशिष्ट पालन के लिए दायर मुकदमे के पक्ष में फैसला सुनाया।

2.6. उपर्युक्त डिक्री से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने 'सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908' (संक्षेप में "संहिता") की धारा 96 के तहत अपील दायर करके उसे चुनौती दी। अपील के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी द्वारा संहिता के 'आदेश XLI

नियम 27(1)' के प्रावधानों के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। उसने अपील के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग की। जो दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने थे, वे निम्नलिखित थे:-

1. मकान संपत्ति सं० 13, पुराना सं० 29/30, ई 6th स्ट्रीट, एच.के.बी रोड, बैंग्लोर 550001 से संबंधित गृह कर मांग रजिस्टर के उद्धरण की प्रमाणित प्रति।
2. मकान संपत्ति सं० 13, पुराना सं० 29/30, ई 5th स्ट्रीट, एच.के.बी रोड, बैंग्लोर 550001 से संबंधित भार प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।
3. ई 5th स्ट्रीट, एच.के.बी रोड, बैंग्लोर 550001 की 22 अक्टूबर 1948 की विक्रय-विलेख की प्रमाणित प्रति।
4. नगर सर्वेक्षण पृष्ठांकन की प्रमाणित प्रति।

2.7. वादी पक्ष ने इस आवेदन का विरोध किया। अपील पर विचार करते हुए, हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने यह फैसला दिया कि वाद-पत्र के पैराग्राफ 9 में दिए गए कथनों को देखते हुए–जिसमें वादियों ने कहा था कि उन्होंने वाद वाली संपत्ति को खरीदने के लिए अपनी अचल संपत्तियां बेच दी थीं, और बाद में प्रतिवादी को यह जानकारी मिली कि ऐसी कोई बिक्री हुई ही नहीं थी–अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति देना ज़रूरी था। इन बातों पर विचार करने के बाद, हाई कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि 20.02.1995 का समझौता साबित नहीं हुआ था और वादियों द्वारा पेश किया गया मामला सच नहीं था। इसी आधार पर, हाई कोर्ट ने 'विशिष्ट पालन' के आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादी को निर्देश दिया कि वह वादी नंबर 1 से उधार ली गई ₹1,00,000 की राशि लौटा दे।

3. अपीलकर्ताओं-वादियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राघवेंद्र श्रीवत्स ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री को पलटना हाई कोर्ट के लिए उचित नहीं था। वादियों ने 20.02.1995 की तारीख वाले समझौते के अनुसार, अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए अपनी तत्परता और इच्छाशक्ति को न केवल अपने अभिवचनों में प्रस्तुत किया था, बल्कि उसे सिद्ध भी किया था। ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद समस्त साक्ष्यों की जांच करने के बाद, यह सही निष्कर्ष दिया था कि 20.02.1995 की तारीख वाला समझौता विधिवत रूप से सिद्ध हो चुका है, और इस निष्कर्ष को पलटने में हाई कोर्ट से त्रुटि हुई है।

प्रतिवादी ने उक्त समझौते पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार कर लिया था, इसलिए हाई कोर्ट के लिए यह अनुमेय नहीं था कि वह हस्ताक्षरों की तुलना करे और उसके बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाए। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त साक्ष्य को वादियों को उसका खंडन करने का कोई अवसर दिए बिना ही स्वीकार कर लिया गया। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि पक्षों की सुनवाई होने और निर्णय सुरक्षित रख लिए जाने के बाद, हाई कोर्ट द्वारा विवादित निर्णय सुनाने में काफी विलंब किया गया। इस संबंध में **अनिल राय बनाम बिहार राज्य, (2001) 7 एस.एस.सी 318** और **रतिलाल झावरभाई परमार और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य, 2024 आई.एन.एस.सी 801** के निर्णयों पर भरोसा किया गया। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलीय न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के सुविचारित निर्णय को पलटने में त्रुटि की थी।

4. इसके विपरीत, उत्तरदाता - डिफेंडेंट की ओर से विद्वान सीनियर एडवोकेट, सुश्री महालक्ष्मी पावनी ने विवादित फैसले का समर्थन किया। उनके अनुसार, हाई कोर्ट का यह फैसला सही था कि 20.02.1995 के एग्रीमेंट के साबित होने की बात को पलट दिया जाए। यह प्रतिवादी के बयान से साफ़ था, जिसने तीन जगहों पर अपने दस्तखत तो माने थे, लेकिन 20.02.1995 के दस्तावेज़ पर बाकी दस्तखतों से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में "1872 का अधिनियम") की धारा 73 के तहत मिली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दस्तखतों की तुलना करने का काम सही किया था। चूंकि प्रतिवादी को यह पता चल गया था कि वादियों ने कोई भी अचल संपत्ति नहीं बेची थी, जैसा कि उन्होंने दावा किया था, इसलिए प्रतिवादी ने संहिता के आदेश XLI नियम 27 के प्रावधानों के तहत अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति मांगने वाला आवेदन दिया था। हाई कोर्ट ने इसे सही तरीके से मंज़ूर कर लिया था और राज्य के अधिकारियों से मिले सार्वजनिक दस्तावेज़ों पर विचार करने के बाद, उन्हें भी ध्यान में रखा गया। चूंकि हाई कोर्ट ने पूरे सबूतों पर सही नज़रिए से विचार किया था, इसलिए विवादित फैसले में दखल देने का कोई कारण नहीं था। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि अपील खारिज किए जाने लायक है।

5. पक्षों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेज़ी साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद, सबसे पहले इस बात पर विचार करना आवश्यक होगा कि क्या हाई कोर्ट द्वारा प्रतिवादी को अपील में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देना उचित था; क्योंकि यही वह मुख्य कारण है

जिसके चलते प्रतिवादी द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए अतिरिक्त साक्ष्यों के आधार पर, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आज्ञप्ति को पलट दिया है।

5.1. वाद-पत्र के पैराग्राफ 9 में, वादियों ने विशेष रूप से यह अभिवचन किया था कि उन्होंने वाद-सम्पत्ति को खरीदने के उद्देश्य से अपनी मूल्यवान अचल सम्पत्तियों का विक्रय कर दिया था, जिसकी उन्हें अपने सद्भावपूर्ण उपयोग एवं अधिभोग के लिए आवश्यकता थी। लिखित कथन में, प्रतिवादी ने पैराग्राफ 11 में यह कहा कि वाद-पत्र के पैराग्राफ 9 में अंतर्विष्ट कथनों के संबंध में, प्रतिवादी के ज्ञान में यह बात नहीं थी कि वादियों ने अपनी मूल्यवान अचल सम्पत्तियों को इसलिए बेचा था ताकि उससे प्राप्त राशि का निवेश वाद-सम्पत्ति को खरीदने में किया जा सके।

5.2. वादी नंबर 1 ने अपने बयान में कहा कि चूंकि वह विवादित संपत्ति को अपने रहने के लिए खरीदना चाहता था और बेंगलुरु में उसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं थी, इसलिए उसने बिक्री समझौते की तारीख से एक महीना पहले अपना एक घर बेच दिया था, ताकि वह प्रतिवादी को भुगतान कर सके। अपनी जिरह में, उसने बताया कि 20.02.1995 से लगभग दो महीने पहले, वादी नंबर 2 ने उसे बेंसटन टाउन में स्थित अपनी संपत्ति बेचने के लिए अधिकृत किया था। तदनुसार, उस संपत्ति का कुछ हिस्सा श्री आर. मकबूल को ₹7 लाख में बेचा गया, जबकि शेष हिस्सा श्री गुलज़ार अहमद को ₹2.5 लाख में बेचा गया। उसने आगे यह भी बताया कि बिक्री से प्राप्त राशि को किस तरह से निवेश किया गया था।

5.3. विचारण न्यायालय ने वादी संख्या 1 और अन्य गवाहों के साक्ष्य के साथ-साथ प्रतिवादी के साक्ष्य के आधार पर, वादियों के मामले को स्वीकार कर लिया और विशिष्ट पालन के लिए आज्ञप्ति प्रदान की।

5.4. हाई कोर्ट में दायर अपील में प्रतिवादी द्वारा उठाए गए आधारों में, दिनांक 20.02.1995 के दस्तावेज़ को चुनौती दी गई थी; यह कहते हुए कि यह बिक्री का समझौता नहीं था, बल्कि उक्त दस्तावेज़ सुरक्षा के तौर पर निष्पादित किया गया था, क्योंकि प्रतिवादी ने वादी संख्या 1 से ₹1,00,000 का ऋण लिया था।

5.5. जैसा कि ऊपर बताया गया है, हाई कोर्ट में अपील लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी ने संहिता के आदेश XLI नियम 27(1) के प्रावधानों के तहत आवेदन दायर किया। हाई कोर्ट का यह मत था कि वादपत्र के पैराग्राफ 9 में दिए गए कथनों और वादी संख्या 1 के साक्ष्य के आधार पर, हाउस टैक्स मांग रजिस्टर के अंश, भार प्रमाण पत्र, विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति और सिटी सर्वे पृष्ठांकन की प्रमाणित प्रति के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज़ ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ थे, जिन्हें अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में विचारार्थ

लिया जाना आवश्यक था। इसमें आगे यह भी कहा गया कि सार्वजनिक दस्तावेज़ होने के कारण, 1872 के अधिनियम की धारा 74 के तहत इन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये दस्तावेज़ संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सामान्य क्रम में ही तैयार और संधारित किए जाते हैं। इन्हीं कारणों से, हाई कोर्ट का यह मत था कि अतिरिक्त साक्ष्य दर्ज करने के लिए कार्यवाही को ट्रायल कोर्ट को वापस भेजना (रिमांड करना) आवश्यक नहीं था, और इन दस्तावेज़ों पर स्वयं हाई कोर्ट द्वारा ही विचार किया जा सकता था। तदनुसार, विशिष्ट पालन के लिए पारित डिक्री को उलट दिया गया, और उसके स्थान पर प्रतिवादी को वादी संख्या 1 को ₹1,00,000 की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया।

6. वाद-पत्र के पैराग्राफ 9 में किए गए कथनों और लिखित बयान के पैराग्राफ 11 में उन कथनों पर प्रतिवादी की प्रतिक्रिया को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि जहाँ वादियों ने यह दावा किया था कि उन्होंने इस सौदे को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था हेतु बेन्सन टाउन स्थित अचल संपत्तियों को बेच दिया था, वहीं प्रतिवादी ने यह कहा कि उसे इस तथ्यात्मक पहलू की कोई जानकारी नहीं थी।

7. संहिता के आदेश XLI नियम 27(1) के तहत दायर आवेदन में, प्रतिवादी ने कहा कि उसे यह जानकारी मिली थी कि जून 2000 के अंतिम सप्ताह में वादियों द्वारा ऐसी कोई बिक्री नहीं की गई थी। सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में पूछताछ करने के बाद, उसे यह जानकारी मिली और उसने उक्त दस्तावेजों के अंशों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कीं। यह देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने संहिता के आदेश XLI नियम 27(1) के प्रावधानों के तहत आवेदन पर विचार करना शुरू कर दिया, बिना इस बात की जांच किए कि क्या प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त साक्ष्य का समर्थन प्रतिवादी के लिखित बयान में की गई अभिवचनों द्वारा किया गया था।

8. हमारी राय में, यह विचार करने से पहले कि क्या कोई पक्ष संहिता के आदेश XLI नियम 27(1) के तहत अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का हकदार है, सबसे पहले उस पक्ष के अभिवचनों (pleadings) की जांच करना आवश्यक होगा। ऐसा इसलिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या प्रस्तुत किया जाने वाला मामला इस तरह से अभिवचित किया गया है कि वह रिकॉर्ड पर लाए जाने वाले अतिरिक्त साक्ष्य का समर्थन कर सके। इस संबंध में आवश्यक अभिवचनों के अभाव में, किसी पक्ष को अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देना एक अनावश्यक कवायद होगी; और यदि ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत भी किया जाता है, तो उसका कोई

परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि ऐसे साक्ष्य को विचार में लेना शायद अनुमेय न हो। इस संबंध में, बछराज नाहर बनाम नीलिमा मंडल और अन्य (ए.आई.आर 2009 एस.सी 1103) और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इब्राहिम उद्दीन और अन्य ((2012) 8 एस.एस.सी 148) के निर्णयों का संदर्भ लेना उपयोगी होगा। अतः, संहिता के आदेश XLI नियम 27(1) द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त, अपीलीय न्यायालय के लिए उस पक्ष के अभिवचनों पर विचार करना भी आवश्यक होगा जो ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है। केवल उसके बाद ही, जब न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाए कि संहिता के आदेश XLI नियम 27(1) के प्रावधानों के अनुरूप कोई मामला बनता है, तब ही ऐसी अनुमति प्रदान की जा सकती है। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी जांच न किए जाने के कारण, हमारी यह राय है कि प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दायर किए गए आवेदन को स्वीकार करके न्यायालय ने त्रुटि की है।

9. जैसा कि हमने पाया है कि अतिरिक्त सबूत पेश करने की अर्ज़ी पर अपीलीय अदालत ने इस पहलू की जाँच किए बिना ही विचार कर लिया कि क्या पेश किए जाने वाले अतिरिक्त सबूत प्रतिवादी के कथनों के अनुरूप थे और क्या उसने ऐसा कोई मामला उठाया था; साथ ही, यह तथ्य भी है कि डिक्री को पलटते समय अदालत ने रिकॉर्ड पर लिए गए अतिरिक्त सबूतों को भी ध्यान में रखा है। इसलिए, इस मामले पर हाई कोर्ट द्वारा फिर से विचार किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि हम पाते हैं कि इस मामले पर हाई कोर्ट द्वारा नए सिरे से विचार किए जाने की ज़रूरत है, इसलिए हमने हाई कोर्ट द्वारा अपील का फैसला करने में हुई देरी के पहलू पर विचार नहीं किया है, जैसा कि अपीलकर्ताओं की ओर से ज़ोर देकर कहा गया था।

10. ऊपर बताए गए कारणों से, हम पाते हैं कि जिस फ़ैसले को चुनौती दी गई है, वह क़ानून की नज़र में सही नहीं है। इस अपील पर, प्रतिवादी द्वारा कोड के आदेश XLI नियम 27(1) के प्रावधानों के तहत दायर अर्ज़ी के साथ, नए सिरे से विचार किए जाने की ज़रूरत है। इसलिए, आर.एफ.ए सं० 440/2000 में 30.12.2008 को दिया गया फ़ैसला और आदेश रद्द किया जाता है। इस मामले को High Court को वापस भेजा जाता है, ताकि वह क़ानून के मुताबिक़ इस पर नए सिरे से विचार करे। चूंकि यह मुक़दमा 1997 में दायर किया गया था, इसलिए हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह आर.एफ.ए सं० 440/2000 पर विचार करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाए। यह साफ़ किया जाता है कि हमने इस मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर नहीं की है।

11. उपर्युक्त शर्तों पर सिविल अपील स्वीकार की जाती है, जिसमें पक्षकार अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे।

12. लंबित आवेदन (यदि कोई हों) भी निस्तारित माने जाएंगे।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।